



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 20 पटना, बुधवार, 13 ज्येष्ठ, 1931 (श०)  
3 जून, 2009 (ई०)

### विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-3	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक
		पूरक-क
		5-7

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर  
(स्थापना शाखा)

अधिसूचना  
15 मई 2009

सं०22-06/92-549/स्था०—श्री ललित कुमार दास, अंचल अधिकारी, नवगछिया को दिनांक 2 दिसम्बर 2006 से दिनांक 17 दिसम्बर 2006 तक (16 दिनों) पुत्री की चिकित्सा हेतु एवं दिनांक 21 मई 2007 से 16 जून 2007 तक (27 दिनों) अपनी चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के प्रावधानों के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आयुक्त के आदेश से,  
रामनरेश प्रसाद सिंह,  
आयुक्त के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 11—571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# भाग-2

## बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० 4तक०/विविध-307/06-437

उद्योग विभाग

संकल्प

14 मई 2009

विषय — औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के परिशिष्ट-1 की कंडिका-2 (ग) अन्य श्रेणियों के बिन्दू 7 पर अंकित “पर्यटन” को परिभाषित करने के संबंध में।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में उद्योगों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट एवं सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के परिशिष्ट-1 पर परिभाषाएं अंकित किये गये हैं, जिसके अनुसार औद्योगिक इकाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इस श्रेणी में पर्यटन उद्योग को भी सम्मिलित किया गया है, परन्तु पर्यटन उद्योग को विस्तार से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इन इकाइयों को निबंधन आदि में कठिनाई होती है।

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में पर्यटन को निम्नप्रकार परिभाषित किया जाता है।

“पर्यटन” उद्योग का आशय है पर्यटन उद्योग से संबंधित सभी कार्यकलाप यथा-पर्यटन आकर्षण/पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सभी Convention Centre, आर्ट गैलरी, मनोरंजन पार्क, आकाशीय रज्जू पथ, पर्यटन ग्राम स्थापित करना, साउंड एंड लाइट, टूरिज्म को आकर्षित करने हेतु खेल-कूद सुविधा, मनोरंजन क्लब, स्वीमिंग पुल, आवास, सभी श्रेणियों के होटल, मोटल, मार्गीय सुविधाएं, रिसोर्ट्स, योग केन्द्र, यातायात की सुविधा (वायु, स्थल एवं जल यातायात), होटल-कैटरिंग-पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के सभी आधारभूत संरचनाओं की स्थापना, निर्माण, विकास एवं संचालन”।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अशोक कुमार सिन्हा,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 11-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 मई 2009

सं० कौन भी-907/2005-115—श्री ध्रुव नारायण साहू, वाणिज्य-कर पदाधिकारी (बिहार वित्त सेवा), शाहाबाद अंचल, आरा के विरुद्ध कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल से संबंधित आरोपों के लिए उनके पत्रांक शून्य दिनांक 31 जनवरी 2006 के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षापरांत अनाधिकृत अनुपस्थिति सहित अन्य कतिपय प्रमाणित आरोपों के लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 345 दि० 6 सितम्बर 2007 एवं शुद्धि पत्र सं० 401 दिनांक 23 अक्टूबर 2007 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से आदेश निर्गमन की तिथि से रोके जाने का दंड संसूचित किया गया।

श्री साहू के पत्रांक शून्य दिनांक 12 मई 2008 के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन की सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा उपरोक्त निर्गत दंड को निरस्त करते हुए उन्हें “चेतावनी” की सजा देने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0)—अस्पष्ट,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

मानव संसाधन विकास विभाग

आदेश

12 फरवरी 2009

सं० 3/आ2-017/96-45—श्री प्रेमशंकर श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, गया एवं पटना, सम्प्रति सेवानिवृत्त प्राचार्य, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, अललपट्टी, दरभंगा को गया एवं पटना जिले के पदस्थापनकाल संबंधी आरोपों को विभागीय आदेश सं० 948, दिनांक 28 अक्टूबर 2002 द्वारा प्रथम द्रष्टव्या दोषी मानते हुये लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 49ए के तहत निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया। पश्चात् विभागीय आदेश सं० 42, दिनांक 7 फरवरी 2003 द्वारा श्री श्रीवास्तव को निलंबन से मुक्त किया गया। उक्त आरोपों के लिए सरकार के आदेशानुसार विभागीय संकल्प सं० 51 दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. विभागीय आदेश सं० 46, दिनांक 7 फरवरी 2007 द्वारा नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों साक्ष्यों के आभाव में अप्रमाणित पाये गये। संचालन पदाधिकारी द्वारा

समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार के आदेशनुसार विभागीय आदेश सं० 696, दिनांक 30 जुलाई 2008 द्वारा श्री श्रीवास्तव को अरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया गया।

3. चूँकि श्री श्रीवास्तव आरोपमुक्त किये जा चुके हैं, अतः बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 05 के नियम 11(3) के तहत निलंबन अवधि दिनांक 28 अक्टूबर 2002 से दिनांक 7 फरवरी 2003 में भुगतान की गई जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त शेष वेतन एवं भत्ता भुगतान होगा तथा सी०सी०ए० रूल्स 05 के नियम 11(4) के तहत निलंबन अवधि में कर्तव्य में बिताई गई अवधि मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रण विजय प्रसाद,  
निदेशक (प्र०)-सह-संयुक्त सचिव।

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचनाएं  
12 फरवरी 2009

सं० 3/आ२-31/2001मा०-46—श्री ख्वाजा गुलाम रसूल, तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, प्रटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति प्राचार्य, राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सहरसा के विरुद्ध क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना के कार्यकाल में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, रोहतास में अवैध रूप से नियुक्त लिपिक श्री अली इमाम की सेवा समाप्ति के पश्चात् साजिशपूर्वक उन्हें सेवा में बनाये रखने तथा उनको गलत ढंग से संरक्षण दिये जाने के निमित्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को गलत सूचना देकर उनके वेतन मद में सरकारी कोष से लाखों रुपये का भुगतान करने के षडयंत्र में सम्मिलित होने के आरोपों के लिए बिहार लोक सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प संख्या 280 दिनांक 30 जुलाई 2005 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 423 दिनांक 12 दिसम्बर 2006 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री रसूल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा बृहद् दंड के रूप में “अनिवार्य सेवा निवृत्ति” का दण्ड देने का निर्णय लेते हुए द्वितीय कारण पृच्छा पूछने एवं बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करने का आदेश दिया गया।

4. सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के आलोक में विभागीय पत्रांक 834 दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के द्वारा श्री रसूल से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

5. आरोपी श्री रसूल द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 2 जनवरी 2008 के द्वारा पूछे गये द्वितीय कारणपृच्छा के प्रति उत्तर की समीक्षोपरान्त उसे सरकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए श्री रसूल के विरुद्ध “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” के निर्धारित दण्ड को समुचित एवं न्यायोचित पाया गया।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2609 दिनांक 13 सितम्बर 2006 के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आधिरोपित बृहद् दण्ड “अनिवार्य सेवानिवृत्ति” पर विभागीय पत्रांक 473 दिनांक 27 मई 2008 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी।

7. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3477 दिनांक 17 दिसम्बर 2008 के द्वारा आयोग की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के निर्धारित दण्ड में अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

8. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपी के लिए ख्वाजा गुलाम रसूल, तत्कालीन क्षेत्रीय उप-शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल सम्प्रति प्राचार्य, राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(6) के तहत सरकार ने सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रण विजय प्रसाद,  
निदेशक (प्र०)-सह-संयुक्त सचिव।

13 फरवरी 2009

सं० 3/आ२-27/08मा०-48—श्री दिनेश्वर पासवान, तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध उनके क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल के पदस्थापन अवधि में श्री अली अमाम अवैध रूप से नियुक्त लिपिक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहेबगंज/रोहतास की सेवा समाप्ति के पश्चात् साजिशपूर्वक सेवा में बनाये रखने तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को गलत सूचना देकर वेतन के रूप में सरकारी कोष से लाखों रुपये का भुगतान किये जाने के लिए विभागीय संकल्प

संख्या 282 दिनांक 30 जुलाई 2005 के द्वारा बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच एवं संचालन पदाधिकारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 424 दिनांक 15 दिसम्बर 2006 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ (सेवा काल में) जिसमें जाँच अधिगम में आरोपित पदाधिकारी को दोषी बताया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लेने के क्रम में दिनांक 31 जुलाई 2007 को आरोपित पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प संख्या 282 दिनांक 30 जुलाई 2005 को विभागीय संकल्प संख्या 829 दिनांक 6 दिसम्बर 2007 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत समपरिवर्तित किया गया।

3. विभागीय कार्रवाई में नियुक्त जाँच एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रामाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के अन्तर्गत पेंशन से 20 प्रतिशत कटौती के निर्णयानुसार विभागीय पत्रांक 832 दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. आरोपी श्री पासवान द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 27 दिसम्बर 2007 के द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का प्रतिउत्तर की समीक्षोपरान्त किसी नये तथ्य का समावेश नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए श्री पासवान के विरुद्ध निर्धारित दण्ड पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती को बरकरार रखा गया एवं नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग से निर्धारित दंड पर सहमति प्राप्त करने के निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 472 दिनांक 27 मई 2008 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3479 दिनांक 17 दिसम्बर 2008 के द्वारा अपनी सहमति संबंधी निर्णय संसूचित किया गया, जिसमें सरकार के स्तर से निर्धारित दंड पेंशन से 20 प्रतिशत कटौती को घटाकर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) कटौती करने का परामर्श दिया गया। इसके लिए यह आधार दिया गया कि श्री पासवान सीधे जिम्मेवार नहीं थे।

6. चूँकि विभागीय कार्यवाही में श्री पासवान के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, जिसमें सरकारी राशि की क्षति हुई है। अतएव सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से शतप्रतिशत सहमत नहीं होते हुये श्री दिनेश्वर पासवान, तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमण्डल सम्प्रति सेवा निवृत्त विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को बिहार पेंशन नियमावली के तहत उनके पेंशन से दंड स्वरूप 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) कटौती करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रण विजय प्रसाद,  
निदेशक (प्र०)—सह—संयुक्त सचिव।

19 फरवरी 2009

सं० 3/आ1-10/04-56—विभागीय अधिसूचना सं० 609, दिनांक 11 जुलाई 2008 के द्वारा श्री चन्द्रशेखर कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, औरंगाबाद सम्प्रति, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (डायट) नवादा को 'निन्दन' की सजा देते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया था।

2. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री चन्द्रशेखर कुमार द्वारा अपने पत्रांक कैम्प 01, दिनांक 9 जनवरी 2009 द्वारा पुनर्विचार हेतु एक आवेदन दिया गया। श्री कुमार के आवेदन पर समुचित विचारोपरान्त सरकार द्वारा निन्दन की सजा के स्थान पर चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार निन्दन के दण्ड को संशोधित करते हुए श्री कुमार को चेतावनी के साथ यह हिदायत दी जाती है कि भविष्य में वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहेंगे। इसी के साथ उनके आवेदन को निष्पादित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रण विजय प्रसाद,  
निदेशक (प्र०)—सह—संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 11-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>